डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 अप्रैल, 2026, डिस्पेच दिनांक 16 अप्रैल, 2026

| वर्ष 69 | अंक 22 | भोपाल | 16 अप्रैल, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मंत्री श्री सारंग के मार्कफेड को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश

बंद इकाइयों के पुनरुद्धार और संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग पर भी जोर

10.80 लाख मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य

पैक्स केंद्रों पर किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश

राज्य सहकारी विपणन संघ की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) कार्यालय में समीक्षा बैठक में संघ की गतिविधियों, उर्वरक वितरण व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, परिसंपत्तियों के उपयोग एवं व्यवसाय विस्तार की विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मार्कफेड को आत्मनिर्भर, आधुनिक एवं व्यावसायिक रूप से मजबूत संस्था बनाने के लिए सभी अधिकारी लक्ष्य आधारित कार्य करें। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, बंद औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारंभ करने, संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग करने तथा गोदामों के पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उर्वरक (खाद) प्रबंधन एवं वितरण

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष 10.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 23 मार्च तक 6.70 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है। किसानों को स्थानीय स्तर पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री सारंग ने वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करते हुए बैंकों से प्राप्त ऋण एवं लंबित बकाया राशि की शीघ्र वसूली के निर्देश दिए, जिससे उर्वरक कंपनियों को भुगतान में कोई बाधा नहीं आए। उन्होंने कहा कि संस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना प्राथमिकता है।

परिसंपत्ति प्रबंधन एवं डिजिटल ट्रैकिंग

मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि संघ की सभी अचल संपत्तियों की मैपिंग कर उनका विवरण 'संपदा पोर्टल' पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाए। साथ ही अचल संपत्तियों की सुरक्षा एवं व्यावसायिक उपयोग के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर मुख्यालय भेजी जाए। बैठक में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं अन्य स्थानों पर बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को प्रारंभ करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए। उज्जैन स्थित पेट्रोल पंप को तत्काल पुनः प्रारंभ करने तथा मुख्य मार्गों पर स्थित भूमि पर नए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स/पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिये वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। ईईसी एवं एनसीडीसी योजना के पुराने गोदामों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने तथा उपार्जन प्रक्रिया में संघ के 316 गोदामों (क्षमता 7.84 लाख मीट्रिक टन) का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

संगठनात्मक लक्ष्य एवं अनुसंधान

मार्कफेड के कायाकल्प के लिये गठित विशेष अनुसंधान समिति को 15 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। "को-ऑपरेशन एमंग को-ऑपरेटिव्स" के सिद्धांत पर कार्य करते हुए कृषि विपणन आंदोलन को राज्यस्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मार्कफेड के माध्यम से कृषि विपणन आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा तथा संस्था की वित्तीय स्थिति का सटीक आकलन इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूर्ण किया जाएगा। बैठक में राज्य विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत अग्रवाल, सचिव श्री महेंद्र दीक्षित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के क्रियान्वन के लिए राष्ट्रीय कॉन्क्लेव

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए केंद्र, राज्य और विशेषज्ञों का साझा मंथन

सहकारिता को देश के विकास के दूसरे इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 एक व्यापक और दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत करती है

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का किया आह्वान

PACS कंप्यूटरीकरण, विकेंद्रीकृत भंडारण और सहकारी इकोसिस्टम को सशक्त बनाने पर जोर

विशेषज्ञों ने सहकारिता के आर्थिक योगदान को तीन गुना करने की रणनीतियों पर किया मंथन

अंतिम छोर तक किफायती ऋण उपलब्ध कराने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका सबसे अधिक प्रभावी

नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के विजन को साकार करने तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को देश के विकास के सशक्त इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के कार्यान्वयन पथ एवं आगे की राह" विषय पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कॉन्क्लेव में देशभर से नीति-निर्माताओं, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों एवं हितधारकों ने भाग लेते हुए नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया।

इस अवसर पर, राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सहकारिता भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना का एक मजबूत स्तंभ रही है, जिसने दशकों से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बदलते समय, बढ़ती ग्रामीण आकांक्षाओं और विकसित होती अर्थव्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 एक व्यापक और दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत करती है, जो सहकारिता को देश के विकास के दूसरे इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास को गति देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि यह नीति व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है, जिसमें 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति द्वारा 17 बैठकों और 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से देशभर के सुझावों को शामिल किया गया। उन्होंने नीति के प्रमुख स्तंभों का उल्लेख करते हुए कहा कि सहकारिता की नींव को सुदृढ़ करना, सहकारी ढांचे का विस्तार, व्यावसायिक इकोसिस्टम का विकास, पारदर्शी एवं पेशेवर प्रबंधन, सदस्य-केंद्रितता को बढ़ावा, नए क्षेत्रों में विस्तार और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना इसके मुख्य आयाम हैं। उन्होंने राज्यों को अपनी सहकारिता नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी जानकारी दी, जिससे सहकारिता आंदोलन को और गति मिल सके।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

बीज संघ हाइब्रिड बीजों का उत्पादन कर किसानों को बाजार से आधी कीमत पर उपलब्ध कराएगा : मंत्री श्री सारंग

'एम.पी. के चीता बीज' को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने की होगी पहल

नई सीड प्रोसेसिंग यूनिट और किसानों के प्रशिक्षण पर दें विशेष ध्यान

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने राज्य सहकारी बीज एवं विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (बीज संघ) के संचालक मंडल की बैठक में बीज उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा किसानों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बीज संघ द्वारा मक्का, नॉन-जीएम कपास एवं सब्जियों के हाइब्रिड बीजों का उत्पादन एवं विपणन किया जाएगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज बाजार मूल्य की तुलना में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मंत्री श्री सारंग ने बीज संघ के 'चीता बीज' को विश्व स्तरीय ब्रांड के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजों की गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सोशल मीडिया, कृषि मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

बैठक में बताया गया कि बीज प्रसंस्करण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई सीड प्रोसेसिंग यूनिट एवं कलर सॉर्टेक्स मशीनें स्थापित की जाएंगी। प्रथम चरण में यह कार्य गुना एवं खरगोन में प्रारंभ किया जाएगा, जिसे पैक्स एवं सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तारित किया जाएगा।

मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जिन किसानों ने बीज उत्पादन में अच्छा कार्य किया है, उनके माध्यम से अन्य किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बीज उत्पादन योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि बीज संघ आगामी समय में बीज उत्पादन, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण एवं विपणन को मजबूत करते हुए किसानों को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ कार्य करे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संस्थाएं श्रीमती शीला दाहिमा, राज्य विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत अग्रवाल, बीज निगम के प्रबंध संचालक श्री महेंद्र दीक्षित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पैक्स के 10 लाख नए सदस्य बनाने योजनाबद्ध कार्य करें : प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा

अपेक्स बैंक में 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ की हुई बैठक

भोपाल : अपेक्स बैंक में प्रदेश के 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव सहकारिता एवं प्रशासक अपेक्स बैंक श्री डी.पी. आहूजा ने केसीसी व ऋण वितरण, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, अमानत संग्रहण आदि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी सीईओ आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 10 लाख नये सदस्यों को पैक्स के माध्यम से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर योजनाबद्ध रणनीति बनाकर कार्य करें।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में वर्तमान में भले ही चुनौतियां अधिक हों, लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक एवं लाभप्रद परिणामों से मध्यप्रदेश का सहकारी साख आंदोलन अत्यंत सुदृढ़ एवं सशक्त बनेगा।

श्री आहूजा ने यह भी अपेक्षा की कि आप अपने बैंक के प्रशासक के सतत संपर्क में रहकर विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत शासन से प्राप्त होने वाली राशियों का जमा (डिपॉजिट) अपनी जिला बैंक में सुनिश्चित कराने का प्रयास करें। इसके लिए यदि कहीं शासन स्तर पर मदद की आवश्यकता हो, तो अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक के माध्यम से अवगत कराएं, ताकि यथासंभव आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गबन एवं धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कठोर प्रशासनिक दंड देने में कोई ढील न दी जाए, ताकि आपकी बैंक/संस्था बेहतर व सुचारू रूप से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सफल हो और प्रदेश का सहकारी आंदोलन "सहकार से समृद्धि" की दिशा में प्रगति - पथ पर अग्रसर हो।

बैठक में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने निर्देश दिए कि पैक्स स्तर पर नये सदस्यों की पहचान की जाए। इसके लिए अपेक्स बैंक स्तर से एक निर्धारित प्रारूप भेजा गया है, जिसके अंतर्गत दिनांक 14 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक अभियान चलाकर उक्त प्रारूप में संपूर्ण विवरण भरते हुए शेयर पूंजी के लिए प्रति सदस्य 600 रुपये एकत्रित किए जाएं। इस राशि की प्राप्ति रसीद सदस्य को तत्काल प्रदान की जाए एवं समय पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि भी दर्ज की जाए।

उन्होंने बताया कि इसके लिए नाबार्ड से प्रति कैम्प 1000 रुपये प्राप्त होंगे, किंतु इसके लिए विधिवत दस्तावेजीकरण करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रति सोसायटी लगभग 200 नये सदस्य बनाने होंगे, जिससे 10 लाख नये सदस्यों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

श्री गुप्ता ने यह भी निर्देश दिए कि बैंक अंतर्गत गबन एवं धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति अटैच करने हेतु धारा 64 के अंतर्गत शीघ्र ही अपने जिले के उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया जाए, जिससे संबंधित व्यक्ति से गबन/धोखाधड़ी की राशि की वसूली संभव हो सके।

कृषि केवल आजीविका नहीं, हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था की है धुरी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के साथ जोड़ा जय अनुसंधान

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि केवल आजीविका नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है और प्रदेश के समग्र विकास का आधार भी है। उन्होंने कहा कि आज कृषि एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, मृदा की घटती उर्वरता और बाजार की अस्थिरता जैसी चुनौतियां हमें नई सोच और नवाचार की ओर प्रेरित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाओं का विस्तार हुआ है, तकनीक को खेतों तक पहुंचाया गया है और नवाचार को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है। "ड्रोन दीदी" जैसी पहल केमाध्यम से महिलाएं भी आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ रही हैं, वहीं कृषि सखियों के माध्यम से जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "कृषिःमूलंजीवनम्" का भाव हमारे समाज की जीवन -दृष्टि को व्यक्त करता है। कृषि धन्य है, पवित्र है और जीवन का मूल आधार है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए "समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश" की थीम पर पूरे वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को भविष्य की कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना और कृषि को लाभकारी, स्थायी तथा तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल में परिवर्तित करना है।

एग्री स्टैक योजना में म.प्र. अग्रणी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है। एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत किसानों का संपूर्ण डेटा डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है और इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा है। डिजिटल किसान डेटा इंटीग्रेशन से किसानों की जमीन, फसल और उत्पादन से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से किसानों को मौसम, बाजार भाव और फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की भावना के अनुरूप जय जवान-जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ा गया था और वर्तमान दौर में इसमें "जय अनुसंधान" को भी जोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनि कतकनीक, वैज्ञानिक खेती, कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन और बेहतर मार्केट लिंकेज के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में खेती में नवीन पद्धतियों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। रसायन मुक्त खेती, जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि अवशेषों अर्थात पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन, मंडियों के आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कृषि को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कृषक परिवारों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सके और शहरी परिवारों को ग्रामीण संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही फूड प्रोसेसिंग और एग्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे के माध्यम से फसलों की निगरानी भी की जा रही है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स

का विस्तार, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण के लिए नरवाई प्रबंधन तथा जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी कृषि का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सहायता सीधे किसानों के खातों में पहुंच रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के साथ कृषि को नई दिशा देने का संकल्प ही प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

किसानों के हित में किये जा रहे कार्य

- पीएम किसान सम्मान एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 84 लाख से अधिक किसानों के खातों में प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की सहायता।
- गेहूं उपार्जन पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस।
- धान पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि।
- मूंग-उड़द की एमएसपी पर खरीदी तथा उड़द पर 600 रुपये बोनस।
- आपदा प्रभावित 24 लाख से अधिक किसानों को 2106 करोड़ रुपये की राहत।
- पहली बार सोयाबीन का एमएसपी पर उपार्जन और भावांतर योजना में 1500 करोड़ रुपये का भुगतान।
- सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया।
- किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण।
- 1.79 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा।
- पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 32 लाख किसानों को सोलर पंप।
- सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना से सोलर बिजली से आय का अवसर।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किसानों को 5 एचपी तक मुफ्त बिजली।
- 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन।
- हर साल 10 लाख नए कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था।
- कोदो और कुटकी का क्रमशः 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर उपार्जन
- 1000 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस।
- कृषि से जुड़े उद्योग लगाने वालों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी।
- इन इकाइयों में कार्य करने वालों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन।
- तुअर दाल आयात पर मंडी टैक्स समाप्त।

फूलों की खेती से नई आय

प्रदेश में 44 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती का विस्तार किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी बढ़ रहा है।

एक जिला–एक उत्पाद को प्रोत्साहन

प्रदेश के 7 जिलों के विशेष उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके विपणन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक की नाबार्ड चेयरमैन से शिष्टाचार भेंट

भोपाल : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष श्री शाजी कृष्णन से भोपाल प्रवास पर अपेक्स बैंक, भोपाल के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने भेंट कर मध्यप्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी.सरस्वती, अपेक्स बैंक के उप महाप्रबंधक श्री के.टी.सज्जन, ओ.एस.डी.श्री अरविंद बौद्ध भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान श्री गुप्ता ने मध्यप्रदेश में पैक्स एवं सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु किये जा रहे कार्यों से नाबार्ड अध्यक्ष को अवगत कराते हुए, नाबार्ड से भी इस दिशा में योजनाएं बनाने का अनुरोध किया।

कृषि, परंपरा और नवाचार के समन्वय से मध्यप्रदेश बना कृषि विकास का अग्रणी राज्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

कृषि आजीविका का साधन ही नहीं, भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति का है मूल आधार

किसानों को आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक खेती और बेहतर मार्केट लिंकेजेस से सशक्त कर रही है राज्य सरकार

किसानों के अनुभव, विज्ञान के नवाचार, सरकार की नीतियों और बाजार की संभावनाओं को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है कृषि मंथन कार्यशाला

"समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश" की थीम के साथ पूरे वर्ष प्रदेश में मनाया जा रहा है कृषि उत्सव

राज्य सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए संकल्पित भाव से बढ़ रही है आगे

मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 10 स्टा-र्टअप उद्यमियों को प्रशिस्त-पत्र किए वितरित

23 करोड़ रूपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की दी सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला को किया संबोधित

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। मध्यप्रदेश में कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों को सह अस्तित्व की दृष्टि से बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश की थीम के साथ पूरे वर्ष प्रदेश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा है। कृषि के माध्यम से हमें प्रकृति के साथ जीने का अवसर मिलता है। देश में कृषि की परंपरा लाखों साल पुरानी है। भीम बैठिका में पुरातन काल से कृषि की परंपरा के शैलचित्र देखने को मिलते हैं। हमारे ऋषि-मुनियों ने हजारों सालों से कृषि के साथ जीने का मार्ग दिखाया है। भारतीय संस्कृति में खेती के प्रति आदर का भाव है। देश की धरती अन्न के रूप में सोना उगल रही है। देश में कभी अनाज का संकट आया था, लेकिन आज हमारे कृषि वैज्ञानिक नई-नई किस्में विकसित कर अनाज उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए संकल्पित भाव के साथ आगे बढ़ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की भावना के अनुरूप जय किसान, जय जवान में जय विज्ञान जोड़ा गया था, वर्तमान दौर में हम, इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ रहे हैं। प्रदेश में किसानों को हम केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और बेहतर मार्केट लिंकेजेस से भी सशक्त बना रहे हैं। कृषि मंथन कार्यशाला किसानों के अनुभव, विज्ञान के नवाचार, सरकार की नीतियों और बाजार की संभावनाओं को एक सूत्र में पिरोने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा गौमाता का पूजन कर कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर उन्नत बीज प्रसंस्करण, औषधीय पौध प्रजाति, खाद्य प्रसंस्करण एवं उन्नत कृषि फसलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य एवं वाद्य यंत्रों से स्वागत किया।

इन विकास कार्यों की दी सौगातें

मुख्यकमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में 23 करोड़ 21 लाख की लागत के विभिन्नअ कार्यों का लोकार्पण कर विकास की सौगाते दी। इनमें प्रमुख रूप से 13 करोड़ रूपये की लागत से बने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वीविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन, 1.11 करोड़ रूपये लागत के बोहानी गन्ना अनुसंधान केन्द्रस के प्रशासनिक भवन, 1 करोड़ रूपये लागत के बालाघाट जिले के कृषि महाविद्यालय वारासिवनी के कौशल विकास केन्द्र के साथ ही जबलपुर में 1.26 करोड़ रूपये से बने स्व चालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केन्द्र का लोकार्पण किया। साथ ही किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 4 करोड़ 92 लाख रूपये से निर्मित 4 इकाइयों का भी लोकार्पण किया गया, इसमें रीवा एवं शहडोल के ज्ञान प्रसार केन्द्र शामिल है।

कृषि स्टार्ट-अप्सर के साथ ही विभिन्नै योजना के हितग्राहियों को हितलाभ का किया वितरण

मुख्यवमंत्री डॉ. यादव ने कार्यशाला में भारत सरकार द्वारा वित्तत पोषित 10 स्टा र्ट-अप्सव को 10 करोड़ रूपये से अधिक के स्वीकृति आदेश का वितरण किया। साथ ही कृषक अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृअष्टव कार्य करने को लेकर पीपीव्हीथ, एफआर ऑथॉरिटी नई दिल्लीर द्वारा प्रदत्तक प्रमाण पत्र विश्व विद्यालय को प्रदान किया। उन्हों ने कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ ही विभिन्न् विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष में हमें और आगे बढ़ना है। प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे मेहनतकश किसानों ने प्रदेश को दलहन उत्पादन में शीर्ष स्थान दिलवाया, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। अब हम तिलहन और अन्न सहित हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के किसान तीसरी फसल भी ले रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराये जाएंगे। इससे हमारी कृषि उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। राज्य सरकार पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, आधुनिक यंत्र सभी को साथ जोड़कर किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ा है। मध्यप्रदेश, देश में सर्वाधिक प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य है। बाबा महाकाल के प्रसाद में रागी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार दूध उत्पादन से किसान की आय बढ़ा रही है। खेती और पशुपालन एक सिक्के के दो पहलु हैं। अभी प्रदेश में 9 प्रतिशत दूध का उत्पादन होता है, इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में दूध की खपत भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। शासकीय स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं तक के बच्चों को नि:शुल्क दूध के पैकेट बांटने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन की अलग-अलग योजना पर कार्य कर रही है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक नई किस्मों के विकास में पोषकता पर विशेष जोर दे रहे हैं। प्रदेश में गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड बना है। मध्यप्रदेश ने गेहूँ उत्पादन में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

TOT प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न, सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर रहा विशेष फोकस

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल में दिनांक 07 से 08 अप्रैल 2026 तक दो दिवसीय TOT (Training of Trainers) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक एवं श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण कौशल का विकास एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण था।

कार्यक्रम का शुभारंभ पंजीयन, स्वागत एवं रूपरेखा प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों का Entry Testभी आयोजित किया गया।

श्री श्रीकुमार जोशी (सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक, सहकारिता विभाग) द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन की सहकारिता नीति पर व्यापक एवं तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत की गई। उन्होंने सहकारिता आंदोलन के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान संरचना एवं शासन की विभिन्न योजनाओं—जैसे बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ, PACS सुदृढ़ीकरण, डिजिटलीकरण एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहकारिता की भूमिका—पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो किसानों को सस्ती ऋण सुविधा, विपणन, भंडारण एवं मूल्य संवर्धन जैसी सेवाएँ प्रदान कर उनकी आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। साथ ही उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों—जैसे प्रबंधन दक्षता की कमी, पारदर्शिता का अभाव, सीमित व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं तकनीकी पिछड़ापन—की ओर ध्यान आकर्षित किया।श्री जोशी ने अपने उद्बोधन में सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमता निर्माण, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तकनीकी उन्नयन एवं सदस्य सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि सहकारी संस्थाएँ नवाचार, पारदर्शिता एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाएं, तो वे ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं।

डॉ.एच. एम. मिश्रा (सेवानिवृत्त, प्रशासन अकादमी, विषय विशेषज्ञ) द्वारा प्रशिक्षकों की भूमिका एवं दायित्वों पर गहन एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि एक प्रभावी प्रशिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं, बल्कि प्रतिभागियों को प्रेरित करने, सहभागिता बढ़ाने एवं सीखने के अनुकूल वातावरण निर्मित करने वाला मार्गदर्शक होता है।

उन्होंने प्रभावी प्रस्तुतीकरण कौशल (Presentation Skills) के अंतर्गत विषय की स्पष्टता, सरल भाषा, आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, समय प्रबंधन एवं श्रोताओं के साथ संवाद स्थापित करने की तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही संचार तकनीकों (Communication Skills) में सक्रिय सुनना (Active Listening), प्रश्न पूछने की कला एवं फीडबैक लेने-देने के महत्व को रेखांकित किया।

डॉ.मिश्रा ने विभिन्न प्रशिक्षण उपकरणों एवं विधियों के व्यावहारिक उपयोग को उदाहरण सहित समझाया, जैसे—

- Lecture Method (व्याख्यान पद्धति) द्वारा मूलभूत जानकारी देना,
- Role Play (भूमिका निर्वहन) के माध्यम से व्यवहारिक परिस्थितियों का अनुभव कराना,
- Case Study (प्रकरण अध्ययन) से समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना,
- PPT Presentation (प्रस्तुतीकरण) द्वारा दृश्यात्मक प्रभाव बढ़ाना,
- Group Discussion (समूह चर्चा) द्वारा सहभागिता एवं विचार-विमर्श को बढ़ावा देना, तथा
- Participatory Learning Methods (सहभागी शिक्षण तकनीक)के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रक्रिया का सक्रिय भाग बनाना।

उन्होंने प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु इन सभी विधियों के संतुलित एवं उद्देश्यपूर्ण उपयोग पर विशेष बल दिया।

श्री व्ही. के. राय (क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ, विषय विशेषज्ञ) द्वारा मत्स्य सहकारी समितियों के प्रभावी संचालन, व्यवसाय विकास एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि मत्स्य सहकारी समितियाँ ग्रामीण एवं जलाशय आधारित आजीविका सृजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जो मछुआरों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।उन्होंने समितियों के सुचारु संचालन हेतु सदस्य सहभागिता, पारदर्शिता, समयबद्ध कार्यप्रणाली एवं वित्तीय अनुशासन को आवश्यक बताया। साथ ही मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज (Fish Seed), संतुलित आहार (Feed Management), जल गुणवत्ता प्रबंधन एवं वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया।

श्री राय ने व्यवसाय विकास के अंतर्गत विपणन व्यवस्था सुदृढ़ करने, मूल्य संवर्धन (Value Addition), कोल्ड चेन विकास, तथा सरकारी योजनाओं एवं अनुदानों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न सफल मत्स्य सहकारी समितियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए Best Practices साझा कीं, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक सीख प्राप्त हुई।

श्री विजयवर्गीय (विषय विशेषज्ञ, दुग्ध महासंघ, भोपाल)द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों के प्रभावी संचालन, दुग्ध व्यवसाय के विस्तार एवं सफल मॉडल्स पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि दुग्ध सहकारी समितियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं किसानों की नियमित आय सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम हैं।

उन्होंने समितियों के सुचारु संचालन हेतु सदस्य आधारित प्रबंधन, पारदर्शिता, गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयबद्ध दुग्ध संग्रहण प्रणाली के महत्व पर बल दिया। साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, संतुलित आहार (Feed Management) एवं डेयरी प्रबंधन की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता बताई।

श्री विजयवर्गीय ने दुग्ध व्यवसाय के विस्तार के अंतर्गत दुग्ध प्रसंस्करण (Milk Processing), मूल्य संवर्धन (जैसे पनीर, घी, दही आदि उत्पाद), ब्रांडिंग एवं प्रभावी विपणन रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सफल दुग्ध सहकारी मॉडलों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए Best Practices साझा कीं, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक समझ विकसित करने में सहायता मिली।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि दुग्ध सहकारी समितियाँ आधुनिक तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं बाजार उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाएं, तो वे किसानों की आय वृद्धि एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

डॉ. ब्रीज़ त्रिपाठी (शिक्षाविद् एवं प्रमाणित प्रशिक्षक)द्वारा प्रशिक्षकों हेतु प्रभावी प्रस्तुतीकरण एवं संप्रेषण कौशल के विकास पर एक अत्यंत इंटरैक्टिव एवं व्यवहारिक सत्र संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि एक सफल प्रशिक्षक के लिए केवल विषय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपनी बात को स्पष्ट, प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

डॉ. त्रिपाठी ने प्रस्तुतीकरण कौशल के अंतर्गत आवाज़ के उतार-चढ़ाव (Voice Modulation), बॉडी लैंग्वेज, नेत्र संपर्क (Eye Contact), आत्मविश्वास एवं समय प्रबंधन के महत्व को विस्तार से समझाया। साथ ही संप्रेषण कौशल को प्रभावी बनाने के लिए सरल एवं स्पष्ट भाषा, उदाहरणों का उपयोग, श्रोताओं की सहभागिता तथा प्रश्नोत्तर तकनीक पर विशेष जोर दिया। सत्र के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि एक प्रभावी प्रशिक्षक को अपने श्रोताओं के स्तर, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार अपनी शैली में लचीलापन रखना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण अधिक रोचक, सहभागी एवं परिणामोन्मुख बन सके।

डॉ. योगेश नामदेव (आई.टी. विशेषज्ञ, CBBO)द्वारा दैनिक एवं कार्यालयीन कार्यों को अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाने हेतु गूगल के उन्नत टूल्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि डिजिटल उपकरणों के समुचित उपयोग से कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

उन्होंने Google Docs, Google Sheets, Google Forms, Google Drive एवं Google Meet जैसे टूल्स के उपयोग को व्यावहारिक उदाहरणों सहित समझाया, जैसे—ऑनलाइन डेटा संकलन, रिपोर्टिंग, दस्तावेज साझा करना, वर्चुअल मीटिंग्स का संचालन।

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पृष्ठ 1 का शेष)

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के क्रियान्वन...

श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुरूप अनेक परिवर्तनकारी पहलें शुरू की हैं, जिनमें PACS को बहुउद्देशीय आर्थिक इकाइयों में विकसित करना, उन्हें 25 से अधिक गतिविधियों में सक्षम बनाना, "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना, श्वेत क्रांति 2.0, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क तथा "भारत टैक्सी" जैसी अभिनव पहलों का क्रियान्वयन शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कॉन्क्लेव नीति के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा और सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेगा।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि देश में 80 हजार से अधिक PACS का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिससे उन्हें बहुउद्देशीय, व्यावसायिक और अधिक उपयोगी इकाइयों में परिवर्तित किया जा सके। उन्होंने कहा कि PACS स्तर पर भंडारण का विकेंद्रीकरण, किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना तथा लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो. एस. महेंद्र देव ने अपने विशेष व्याख्यान में सहकारिता क्षेत्र के योगदान को तीन गुना करने की रणनीतियों पर बल देते हुए कहा कि सहकारिता समावेशी और सतत विकास का एक प्रभावशाली माध्यम बन सकती है। इस अवसर पर, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री सतीश मराठे ने कहा कि अंतिम छोर तक किफायती ऋण उपलब्ध कराने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका सबसे अधिक प्रभावी है।

कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न विषयगत सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, PACS को विकास के इंजन के रूप में सशक्त बनाना, सदस्य शिक्षा, युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी, जैविक उत्पाद बाजार में नेतृत्व तथा सहकारी ऋण एवं बैंकिंग जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। ब्रेकआउट सत्रों और ओपन हाउस चर्चाओं के माध्यम से नीति के क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए तथा समापन सत्र में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

यह राष्ट्रीय कॉन्क्लेव राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण

मंच साबित हुआ, जो सहकारिता क्षेत्र को अधिक सशक्त, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और जन-केंद्रित बनाते हुए "सहकार से समृद्धि" के राष्ट्रीय संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

उन्होंने प्रतिभागियों को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने एवं कार्यालयीन कार्यों में नवाचार लाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कार्य प्रणाली अधिक आधुनिक, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बन सके।

द्वितीय दिवस की शुरुआत पूर्व दिवस के प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति एवं प्रमुख सीख (Key Learnings) पर चर्चा से हुई।

श्री पी. एस. तिवारी (प्राचार्य, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज, भोपाल) द्वारा बी-पैक्स (B-PACS) सहकारी समितियों के प्रभावी संचालन, व्यवसाय विकास एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर विस्तृत एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बी-पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई हैं, जो किसानों को ऋण, कृषि आदान (Inputs), भंडारण एवं विपणन जैसी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं।

उन्होंने बी-पैक्स के सुचारु संचालन हेतु पारदर्शी प्रबंधन, समयबद्ध ऋण वितरण एवं वसूली, लेखा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा सदस्य सहभागिता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही व्यवसाय विकास के अंतर्गत बी-पैक्स को बहुउद्देश्यीय बनाते हुए उर्वरक वितरण, उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउसिंग एवं अन्य आयवर्धक गतिविधियों को अपनाने पर बल दिया।

श्री तिवारी ने सफल बी-पैक्स समितियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए Best Practices साझा कीं तथा बताया कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग, डिजिटलीकरण एवं पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से बी-पैक्स को अधिक सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि बी-पैक्स को समुचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वे किसानों की आय वृद्धि एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

श्री पी. के. एस. परिहार (सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक)द्वारा बी-पैक्स (B-PACS) उपविधियों का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960के साथ सहसंबंध को स्पष्ट करते हुए कानूनी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।उन्होंने बताया कि किसी भी सहकारी संस्था का संचालन उसके उपविधियों (By-laws) के अनुरूप होता है, जो अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। अतः उपविधियों एवं अधिनियम के प्रावधानों के बीच सामंजस्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।श्री परिहार ने सदस्यता, प्रबंधन संरचना, निर्वाचन प्रक्रिया, बैठक संचालन, लेखा परीक्षण (Audit) एवं वित्तीय अनुशासन से संबंधित प्रावधानों को सरल एवं स्पष्ट रूप में समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि बी-पैक्स के सुचारु एवं पारदर्शी संचालन हेतु कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य है, जिससे संस्था की विश्वसनीयता एवं स्थायित्व सुनिश्चित होता है।उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से अभिलेख संधारण (Record Keeping), नियामकीय अनुपालन (Compliance), समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं निरीक्षण प्रक्रियाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

सत्र के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्होंने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जटिल कानूनी प्रावधानों को सरलता से समझाया, जिससे प्रतिभागियों को बी-पैक्स संचालन के कानूनी ढांचे की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई।

डॉ. मनोज कुमार जैन (वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रमुख, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान) द्वारा प्रशिक्षकों में शोधपरक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने पर गहन एवं ज्ञानवर्धक चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एक प्रभावी प्रशिक्षक के लिए केवल जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तथ्यों, आंकड़ों एवं साक्ष्यों के आधार पर विषय की गहराई से समझ विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने साक्ष्य-आधारित प्रशिक्षण (Evidence-Based Training) की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वास्तविक आंकड़ों, केस स्टडी एवं क्षेत्रीय अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी बन सके। डॉ. जैन ने डेटा विश्लेषण (Data Analysis) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सही डेटा के विश्लेषण से समस्याओं की पहचान, समाधान की रणनीति एवं बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का समुचित उपयोग कर प्रशिक्षण सामग्री को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेरित किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रभावी निर्णय क्षमता (Decision Making Skills) विकसित करने पर बल देते हुए तार्किक सोच, समस्या समाधान दृष्टिकोण एवं वैकल्पिक समाधानों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।

सत्र के दौरान उन्होंने उदाहरणों एवं संवादात्मक शैली के माध्यम से प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से शामिल किया, जिससे प्रशिक्षकों में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण एवं शोधपरक सोच विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

श्री गौरव शाक्य (उपनिदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम – NCDC, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल) द्वारा NCDC की विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा सहकारी संस्थाओं, विशेषकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS), दुग्ध, मत्स्य एवं कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) के समग्र विकास हेतु विभिन्न वित्तीय एवं विकासात्मक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से कृषि, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन एवं बहुउद्देश्यीय गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।श्री शाक्य ने PACS सुदृढ़ीकरण, वेयरहाउस निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी एवं मत्स्य विकास जैसी योजनाओं के प्रमुख प्रावधानों, पात्रता मानदंड एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट रूप में समझाया। उन्होंने परियोजना आधारित कार्यप्रणाली अपनाने, गुणवत्तापूर्ण DPR (Detailed Project Report) तैयार करने तथा समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी संस्थाएँ NCDC की योजनाओं का लाभ लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकती हैं, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दे सकती हैं तथा किसानों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

सत्र के दौरान प्रतिभागियों को सफल परियोजनाओं के उदाहरणों के माध्यम से व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया, जिससे उन्हें NCDC योजनाओं के प्रभावी उपयोग की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई।

कार्यक्रम का समापन Exit Testके माध्यम से प्रतिभागियों के प्रशिक्षण उपरांत ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए किया गया। इसके पश्चात प्रतिभागियों से प्रशिक्षण संबंधी फीडबैक प्राप्त किया गया, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की उपयोगिता एवं गुणवत्ता की सराहना की।

समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा सभी विषय विशेषज्ञों, प्रतिभागियों एवं आयोजन से जुड़े अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस प्रकार दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन श्री जी.पी. मांझी प्राचार्य एवं श्रीमती रेखा पिप्पल द्वारा किया गया।

कृषि, परंपरा और नवाचार के समन्वय से मध्यप्रदेश....

प्रदेश में गेहूं का उपार्जन 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है। इसे 2700 रूपए तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित है। प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ मिला है। अब सरसों की फसल पर भी भावांतर का लाभ किसानों को दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान की कल्पना की थी। मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। माँ नर्मदा प्रदेश के किसानों के लिए जीवन रेखा है, जो मध्यप्रदेश के साथ गुजरात और राजस्थान को भी जल देती है। माँ नर्मदा खेती से लेकर उद्योग की जरूरतों और हर कंठ की प्यास बुझाती है। मध्यप्रदेश, देश में कृषि क्षेत्र में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला राज्य बना है। इसमें माँ नर्मदा का विशेष आशीर्वाद शामिल है।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि कृषि मंथन कार्यशाला में देश-विदेश के कृषि वैज्ञानिक, कृषि स्टार्ट-अप, एफपीओ एवं किसान बंधु शामिल हुए हैं। यह मंच कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्यप्रदेश अनेक कृषि फसलों में देश में नंबर-1 है। कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं, सोयाबीन और चना सहित अनेक नई फसलों की किस्में तैयार की हैं। विश्वविद्यालय ने बालाघाट के चिन्नौर चावल और रीवा के सुंदरजा आम के लिए जीआई टैग प्राप्त किए हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के साथ किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद किया, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करना और खेत से कारखानों तक उत्पादों की पहुंच सुगम बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विकास दर को गति देने के लिए क्षेत्रीय अनुकूलता के आधार पर गतिविधियों को सुनिश्चित करने और आधुनिक तकनीकों को किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिये।

संवाद में कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अनुसंधान और नवाचारों पर सारगर्भित चर्चा की, जिसमें कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसल वैरायटी, प्राकृतिक खेती, खरपतवार नियंत्रण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कृषि में उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने पशुधन और पशुचारे के प्रबंधन के माध्यम से किसानों की अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों पर भी अपने विचार साझा किए।

(पृष्ठ 4 का शेष)

राज्यों के साथ केन्द्रीय कृषि मंत्री की समीक्षा बैठक : किसान आईडी, उर्वरक की उपलब्धता और पीएम-आशा के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

19 राज्यों में अब तक 9.25 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं- श्री शिवराज सिंह चौहान

श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों को उर्वरक की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, शिकायतों का समय पर निवारण हो तथा खरीद सीधे किसानों से हो- श्री शिवराज सिंह चौहान

दिल्ली| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर किसान आईडी, उर्वरक की उपलब्धता एवं विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसान आईडी किसानों को उनकी भूमि, फसल, पशुधन एवं मत्स्य पालन से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब तक 19 राज्यों में कुल 9.25 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य सरकारों के कृषि एवं राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अगले 6 महीनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करें। साथ ही व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान रजिस्ट्री केवल पीएम-किसान लाभार्थियों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी पात्र किसानों को शामिल किया जाए।

उर्वरक उपलब्धता पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्यों को जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध हो सके, साथ ही असंतुलित उपयोग को रोकने एवं जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया जाए।

सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि उर्वरक के अवैध आवागमन को रोकना आवश्यक है। हरियाणा के "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पहल की सराहना करते हुए उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया।

पीएम-आशा योजना के अंतर्गत दलहन एवं तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की समीक्षा भी की गई। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकार

दलहन एवं तिलहन की खरीद MSP पर करती है तथा राज्य इसके दिशा-निर्देशों के अनुसार भाग लेते हैं।

हाल ही में विभिन्न राज्यों को निम्नलिखित फसलों की खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान की गई हैं:

आंध्र प्रदेश (चना, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली); असम (सरसों); बिहार (मसूर); छत्तीसगढ़ (चना, मसूर, सरसों); गुजरात (चना, सरसों); हरियाणा (चना, सरसों); कर्नाटक (चना, कुसुम); महाराष्ट्र (चना); मध्य प्रदेश (चना); राजस्थान (चना, सरसों); तेलंगाना (चना, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी); उत्तर प्रदेश (चना, मसूर, सरसों)।

केन्द्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि केवल FAQ (Fair Average Quality) की उपज की खरीद सुनिश्चित की जाए। किसानों का पंजीकरण आधार आधारित पोर्टलों पर किया जाए तथा खरीद केंद्रों पर बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जाए। भुगतान आधार-सक्षम DBT के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में किया जाए और साथ ही खरीद केन्द्रों की भी पर्याप्त संख्या हो जिससे किसान भाई-बहनों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

उन्होंने राज्यों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, शिकायतों का समय पर निवारण हो तथा खरीद सीधे किसानों से हो।

क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पर दी गई ये जानकारी

इसके साथ ही क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित करने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश को पांच एग्रो-क्लाइमेटिक जोन में विभाजित कर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके तहत वेस्टर्न जोन के लिए पहला सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान (VKSA) के बारे में मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष यह अभियान अत्यंत सफल रहा जिसमें 728 जिलों के 60,000 से अधिक गांवों में वैज्ञानिकों ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि पूर्व की सफलता को देखते हुए राज्यों से इस साल भी मई माह में 15–20 दिनों का यह अभियान चलाने का आग्रह किया। इसका उद्देश्य लैब टू लैंड कनेक्ट को मजबूत करना, नई तकनीकों, किस्मों एवं कृषि पद्धतियों का प्रसार करना है।

इस अभियान में Indian Council of Agricultural Research एवं कृषि मंत्रालय का सहयोग रहेगा तथा राज्यों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। प्राथमिकता के क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग, गुणवत्तापूर्ण बीज के प्रति जागरूकता शामिल हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बैठक के अंत में कहा कि किसानों को उचित मूल्य, पारदर्शी खरीद प्रणाली एवं प्रभावी वितरण तंत्र सुनिश्चित करना राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है जिससे कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सके। इस वर्चुअल बैठक में बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पशुपालन की विभिन्न योजनाओं से किसान होंगे आत्मनिर्भर : मुख्यमंत्री

स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति-2025 लागू

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर होंगे। हमारा संकल्प है कि हम प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को निरंतर बढ़ाएंगे और वर्ष 2028 तक प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाएंगे। गो-संरक्षण और गो-संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में पशुपालन विभाग को अब गौपालन विभाग का नाम दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में "स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति-2025" लागू की गई है। इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध गोवंश के आश्रय और भरण-पोषण के लिए 5 हजार से अधिक क्षमता वाली वृहद गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश के आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन जिलों में आदर्श गौशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि भोपाल, जबलपुर और सागर में इनके निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में देश का पहला 100 टन क्षमता वाला सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 9 प्रतिशत योगदान देता है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में सांची ब्रांड को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ करार किया गया है। गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में गौसंवर्धन बोर्ड के माध्यम से गौशालाओं को चारा-भूसा अनुदान के लिए 505 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। गौशालाओं में गोवंश के बेहतर आहार की व्यवस्था के लिए प्रति गोवंश दी जाने वाली सहायता राशि 20 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। घायल अथवा असहाय गायों के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पशुपालन और डेयरी विकास को गति देने के लिए "मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना" का नाम परिवर्तित कर "डॉ. भीमराव अंबेडकर विकास योजना" किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 42 लाख रुपये तक ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें 25 से 33 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रहण को बढ़ाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। दुग्ध संकलन क्षमता को बढ़ाते हुए 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक दुग्ध संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में दूध संकलन कवरेज वाले गांवों की संख्या 9 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने का लक्ष्य है। इसी अवधि में प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।

अब तक प्रदेश में 1,181 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है और 617 निष्क्रिय समितियों को पुनः सक्रिय बनाया गया है। इसमें लगभग 150 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन भी शामिल है। दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर ब्लॉक में एक वृंदावन ग्राम विकसित किया जा रहा है।

गो-संरक्षण और गो-संवर्धन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम और नस्ल सुधार कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन जारी है।

अति पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया के पशुपालकों के लिए प्रदेश के 14 जिलों में मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान पर दो-दो मुर्रा भैंस या गाय प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर, विदिशा और रायसेन जिलों में संचालित किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 1500 "मैत्री" (मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इन सेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया) केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल सुधार का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

सहकार भारती का पर्यटन एवं मत्स्य प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

प्रदेश से आए मछुआरा समाज के लोगों ने जल योद्धा मोहन नागर का किया सम्मान

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के मुख्य आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम

भोपाल। सहकार भारती मध्य प्रदेश के द्वारा विगत दिनों अपेक्स बैंक के ऑडिटोरियम भवन में , मत्स्य एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता स्वयंसेवकों का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता एवं खेल युवक कल्याण मंत्री विश्वास जी सारंग ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ पर्यावरणविद् एवं समाजसेवी जल योद्धा कहे जाने वाले, जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी के साथ किया।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र के अंतराल में मुख्य अतिथि विश्वास सारंग एवं मोहन नागर जी का उद्बोधन हुआ। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने मोहन नागर जी के सम्मान के अवसर पर कहा कि मोहन नागर जी का व्यक्तित्व एवं उन्हें भारत सरकार द्वारा प्राप्त पद्मश्री सम्मान हमारा एवं संपूर्ण पर्यावरण से जुड़े हुए जल संवर्धन एवं संरक्षण के प्रणेता , एवं स्वयंसेवकों का सम्मान है। हमें इस सम्मान पर आत्म सम्मान प्राप्त होता है । विश्वास सारंग जी ने मोहन नगर के व्यक्तित्व के विषय में कार्यक्रम संबोधित करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश के जगह-जगह से पधारे मत्स्य कार्यकर्ता एवं मछुआरा समाज के लोगों को संबोधित करते हुए पर्यटन को भी नई नीति से जोड़ते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश में नई नीति आने के बाद जल को पर्यटन से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर को किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं करने दिया जाएगा। हम पर्यटन को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण संरचना में पर्यटन क्षेत्र को सहकारिता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास पर्यटन समितियां के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इस प्रयास में पर्यटन सहकारी संघ का निर्माण किया गया है , एवं कई जिले इस सहकारी पर्यटन समितियां के माध्यम से जुड़ चुके हैं। निश्चित रूप से बिन सहकार नहीं उद्धार का उद्बोधन हमारे लिए हमेशा से सार्थक सिद्ध हुआ है । सारंग ने कहा कि सहकार भारती का यह प्रयास बेहद सराहनीय एवं ऐतिहासिक है । उन्होंने सरकार भारती के संगठन मंत्री राधेश्याम जल छेत्री जी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि -राधेश्याम जी हमेशा सहकारिता से जुड़े हुए कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ सजक एवं संघर्षशील रहते हैं । अपने उद्बोधनों में उन्होंने पर्यटन सहकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद तोमर की भी तारीफ की।

कार्यक्रम में मछुआरों की उपस्थिति एवं मत्स्य समितियां के विषय में कहा कि -कभी-कभी भगवान को भी भक्तों से कम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।निश्चित रूप से मछुआरा समाज हमेशा उधर के लिए धारण संकल्पित रहा है।

कार्यक्रम में सम्मानित किए गए मोहन नागर जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मछुआरा समाज की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यही वह समाज है जिसने जल संरक्षण एवं संवर्धन के विषय को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए वास्तविक जल संरक्षण एवं संवर्धन को जीवंत किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान , बताया कि उन्होंने जल योद्धा के रूप में जितने भी कार्य किए हैं उस सभी कार्यों में , मछुआरा समाज की भूमिका अभिन्न एवं महत्वपूर्ण रही है । मोहन नागर जी के इस सम्मान के अवसर पर सरकार भारती से जुड़े हुए कई पदाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह गौतम ने सहकार भारती के विषय में तीन वर्ष की प्रति समीक्षा रिपोर्ट , एवं सहकारिता आंदोलन के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि बिन सहकार के उधर नहीं हो सकता है। आता हमें सहकार के विचार को आत्मसात करना होगा।

कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश से आए हुए सभी सहकार भारती से जुड़े हुए पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ताओं के बीच मत्स्य सोसाइटियों एवं पर्यटन सोसाइटियों से पधारे स्वयंसेवक एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन मंत्री ने कहा कि हम सहकारिता के माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष या निवेदन करते हैं कि मछुआरा समाज एवं पर्यटन की प्रगति के लिए किस तरह से विस्तृत रूप रेखा एवं योजना बनाई जा सकती है ।इस पर कार्य करना आवश्यक है। उपरोक्त संबंध में सभी मछुआरों एवं पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा एक ज्ञापन पत्र मंत्री सहकारिता को विश्वास सारंग जी को सौंपने के विषय में भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे । हाल ही में मध्य प्रदेश की नवीन मत्स्य नीति पर सहकार भारती के द्वारा प्रकाश डाला गया। एवं इस कार्यक्रम के दौरान नवीन नीति में पर्यटन एवं मत्स्य संपदा को नए आयाम देने के विषय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उपलब्धि एवं मध्य प्रदेश सरकार की उपरोक्त विषय में उपलब्धि को भी प्रकाश में लाया गया ।कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ संपादक प्रमोद दुबे द्वारा किया गया। मछुआरा समितियों के कार्यकर्ता हुए शामिल ।पर्यटन प्रकोष्ठ, मत्स्य प्रकोष्ठ प्रदेश सम्मेलन भोपाल 2026 में 35 जिलों से 352 संख्या की उपस्थिति रही । 125 मछुवारा सहकारी समिति ने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रीय मंत्री सहकार भारती श्री गजेन्द्र सिंह गौतम जी, प्रदेश संगठन मंत्री सहकार भारती मध्यप्रदेश श्री राधेश्याम जलक्षत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी सहकारिता मंत्री एवं पदमश्री से सम्मानित आदरणीय श्री मोहन नागर जी जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष जी की विशेष उपस्थिति रही। श्री प्रकाश रत्नपारखी जी, श्री अरुण तोमर जी, सुश्री जया श्रीवास्तव जी, श्री धन्ना लाल रायकवार जी, श्री भरत केंवट जी, डॉ मुन्ना लाल केवट, श्री अशोक रायकवार जी, श्री कुंवरअरविन्द सिंह तोमर प्रदेश प्रमुख सहकार भारती पर्यटन प्रकोष्ठ , प्रमोद दुबे विनोद बाथम मानवेंद्र सिंह चौहान गुना पवन श्रीवास्तव पातालकोट महेश चौरासे बैतूल तुषार नारखेड़ बुरहानपुर नरोत्तम धाकड़ शिवपुरी कुलदीप शर्मा धर्मेन्द्र दांगी जी, श्री कैलाश रायकवार जी, श्री कैलाश लुवाना जी, श्री मोहित चौरसिया जी, डॉ रानी रायकवार जी, श्री राधेश्याम कुंभकार जी श्री विवेक जी रायकवार निशा केवट भोपाल , विपिन तोमर मुरैना शंकर लाल गुप्ता आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।